प्रकाशन का 40 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 26 – 3 अक्तूबर 2016 मूल्य पांच रूपए

मनी लांडरिंग प्रकरण में

वीरभद्र और प्रतिभा की संपतियों की प्रोविजनल रिपोर्ट हुई रेगुलर,एक और अटैचमैन्ट की संभावना

अपराजिता और विक्रमादित्य की संपतियों पर है स्टे
वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर, पिचेश्वर गडढे, चुन्नी लाल, राम प्रकाश भाटिया और कमल कुमार कोठारी भी पंहुचे हैं उच्च न्यायालय में
विक्रमादित्य भी बरसे जेटली, धूमल और अनुराग पर

शिमला/शैल। वीरभद्र और अन्य के खिलाफ सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों की जांच के शीघ्र पूरा होने की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि सीबीआई ने तो जांच पूरी करके दिल्ली उच्च न्यायालय से ट्रायल कोर्ट में चालान दायर करने की अनुमति की भी गुहार लगा दी है। इस मामले में वीरभद्र ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए इसमें दर्ज एफ आईआर को रद्द करने की गुहार अदालत से लगा रखी है। इस मामले में अदालत में बहस चल रही हैं वीरभद्र अपना पक्ष रख चुके है और सीबीआई को अब अपना पक्ष रखना है। यदि इसमें दर्ज एफआईआर रद्द न हुई तो इसी सप्ताह सीबीआई का चलान ट्रायल कोर्ट में पंहुच जायेगा। सीबीआई में 28 सितम्बर 2015 को मामला दर्ज हुआ था और एक वर्ष में जांच पूरी करके ऐजैन्सी ने इसे ट्रायल के मुकाम तक पंहुचा दिया है।

दूसरी और ईडी ने इस मामले में अक्तूबर 2015 में मनीलॉरिंग के तहत एफआईआर दर्ज की थी और मार्च 23 को इसमें करीब आठ करोड़ की चल अचल संपत्ति की प्रोविजनल अटैचमैन्ट के आदेश किये थे। दिल्ली उच्च न्यायालय में अटैचमैन्ट के आदेश को चुनौति अपराजिता ने दी थी। इस पर न्यायालय ने अटैचमैन्ट को रद्द न करके इस पर अगली कारवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन 23 सितम्बर को प्रोविजनल अटैचमैन्ट के 180 दिन पूरे होने पर हुए रिव्यू में वीरभद्र और प्रतिभा की संपतियों की अटैचमैन्ट को रेगुलर कर दिया है। क्योंकि उनकी संपतियों पर स्टे नहीं है। इस आदेश के बाद अटैच हुई संपत्ति के सारे लाभों से वीरभद्र परिवार वचिंत हो गया है। राजनीतिक सद्धर्भो में इसे वीरभद्र के लिये एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वीरभद्र के बच्चों ने इस प्रोविजनल आदेश को रद्द करने और इसमें कोई भी अगली कारवाई न किये जाने की अदालत से गुहार लगा रखी थी जिसे नजर अन्दाज करते हुए यह आदेश हुए है। ईडी की जांच में प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोगों का प्रमुख संद्धर्भ आया है उनमें आनन्द चौहान, चुन्नी लाल, वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर, पिचेश्वर गडढे, राम प्रकाश भाटिया और कमल कुमार कोठारी के नाम प्रमुख है। ईडी ने इन सब लोगों से जनवरी 2016 में पूछताछ करके इनके ब्यान दर्ज किये है। पिचेश्वर गड्ढे दंपत्ति से मैहरोली का फार्म हाऊस खरीदा गया है। पिचेश्वर गडढे के 6 जनवरी को ब्यान दर्ज किये गये थे और उसके बाद गड्ढे दिल्ली उच्च न्यायालय में पंहुच गये थे। गड्ढे के बाद अन्य लोग भी उच्च न्यायालय में पंहुच चुके है।

ईडी में अभी तक वीरभद्र पूछताछ के लिये पेश नहीं हुए है जबकि अटैचमैन्ट आदेश से पहले एक दर्जन बार उन्हें नोटिस जारी हुए थे। प्रतिभा सिंह ने जांच में शामिल होने से पहले अदालत से प्रौटैक्शन का आग्रह किया था। यह आग्रह स्वीकार होने के बाद ही वह पूछताछ के लिये गई थी। इसी तर्ज पर विक्रमादित्य सिंह भी अदालत में प्रौटैक्शन का आश्वासन मिलने के बाद ही पूछताछ के लिये पंहुचे। लेकिन इस पुछताछ से बाहर आने के बाद विक्रमादित्य ने जिस अन्दाज में जांच ऐजैन्सी, मोदी सरकार अमित शाह, अरूण जेटली, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर को कोसा है। उससे बाहर यह संदेश गया है कि संभवतः यह पूछताछ काफी तलख रही है।

यदि पूरे प्रकरण पर नजर डाली जाये तो इसके दो भाग सामने आते हैं पहले भाग में आनन्द चौहान के खातों में पांच करोड़ से अधिक का कैश जमा होना और उससे वीरभद्र परिवार के सदस्यों के नाम बीमा पॉलीसीयां लेना तथा आनन्द चौहान द्वारा इस पैसे को वीरभद्र के बगीचे की आय बताना और खुद को बगीचे का मैनेजर कहना शामिल रहा है। इतने भाग की जांच पूरी होकर अटैचमैन्ट आर्डर जारी हुआ। आनन्द चौहान की गिरफ्तारी हुई और उसका चालान भी ट्रायल कोर्ट में पंहुच चुका है। लेकिन अटैचमैन्ट आर्डर में यह कहा गया है कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को लेकर जांच जारी है। चालान में भी अनुपूरक चालान शीघ्र लाने की बात कही गयी है।

अब दूसरे भाग की जांच जारी है। जिसमें वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के नाम चार करोड़ का मुक्त ऋण, वक्कामुल्ला की ही एक कंपनी से एक करोड़ के शेयर खरीदना शामिल है इसी में पिचेश्वर गडढे दंपत्ति से विक्रमादित्य और अपराजिता की कंपनी मैपल डस्टीनेशन के नाम मैहरोली के फार्म हाऊस की खरीद भी शामिल है। इस फार्म हाऊस की रजिस्ट्री 1.20 करोड़ दिखवायी गयी है जबकि जून 2014 में इसी गडढे ने आयकर विभाग की पूछताछ में यह फार्महाऊस 6.81 करोड़ में बेचा जाना और इसमें 5.41 करोड़ कैश में लिया जाना स्वीकारा है। जब 1.20 करोड़ में फार्महाऊस खरीदा गया। उसी दौरान वक्कामुल्ला चन्द्र की कंपनी तारिणी इन्ट्रनेशनल ने विक्रमादात्यि की कंपनी मैपल डस्टीनेशन को 1.20 करोड़ ठेका दिया ऑफिस की रैनोवेशन के लिये। लेकिन इसी दौरान वक्कामुल्ला ने मार्किट से 16 करोड इकट्ठा करने के लिये आईपीओ फ्लोर किये और इसका उद्देश्य भी ऑफिस रेनोवेशन दिखवाया। इसी संद्धर्भ में भाटिया और कोठारी के नाम आये है और आयकर ने भी पूछताछ की है। इसी में रोहतांग सुरंग का निर्माण कर रही Starbag AFCONS JV कंपनी से लाखों का किराया लिया जाना भी शामिल है। आयकर सीबीआई और ईडी जांच में वक्कामुल्ला की वित्तिय स्थिति को लेकर सन्देह व्यक्त किया गया है। क्योंकि विशाखापट्नम की जिस संपत्ति का उसने दावा किया था वह किसी त्रिपूर्णा अहल्या की है। ऐसे में वक्कामुल्ला से जुडे सारे लेनदेन सन्देह के घेरे में है और इन्ही को लेकर विक्रमादित्य से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों को लेकर भी ईडी अटैचमैन्ट आदेश जारी कर रही है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में

26 स्टोन क्रशरों के खिलाफ ई डी में पंहुची शिकायत और जांच रिपोर्ट पर कारवाई कब

शिमला/शैल। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरे विश्व में गंभीर चिन्तन और चर्चा चल रही है। जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 की अवहेलना को Scheduled offence अधिसूचित करने के साथ ही इसे मनीलॉडरिंग एक्ट के दायरे मे ला दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रब्यूलन का गठन भी पर्यावरण पर उठी चिन्ताओ का ही परिणाम है। दिल्ली में डीजल वाहनो पर लगा प्रतिबन्ध और हिमाचल में मनाली से रोहतांग के लिये अब सीएनजी और इलैक्ट्रिक वाहनो का प्रयोग और प्रयास इसी चिन्ता का परिणाम है। राज्यों के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डो के जिम्मे पर्यावरण संरक्षण का ही सबसे बड़ा काम है। इसी के परिणामस्वरूप थर्मल सीमेन्ट प्लांट हिमाचल के लिये ब्लैक उद्योगों को सूची में है। खनन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और इसी लिये प्रदेश उच्च न्यायालय अवैध खनन की शिकायतों पर पूरी कड़ाई से कारवाई कर रहा है।

लेकिन क्या राज्य का प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उद्योग विभाग और केन्द्र का प्रवर्तन निदेशालय इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं या इन पर प्रदेश के खनन माफिया का पूरा दबाव चल रहा है। यह सवाल पिछले कुछ अरसे से चर्चा का विषय बना हुआ है। शैल को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सबसे बडे आद्यौगिक क्षेत्र नालागढ़ उपमण्डल के 26 स्टोन क्रशरों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15,16 और 19 के तहत प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जनवरी 2016 में अतिरिक्त सीजेएम नालागढ की अदालत में मामले दायर किये थे। पर्यावरण अधिनियम के तहत मामले दर्ज होने के कारण इसकी जानकारी शिमला स्थित ईडी कार्यालय तक भी पंहुच गयी। पर्यावरण अवहेलना Scheduled offence होने के नाते ईडी कार्यालय ने भी इसमें अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी।

ईडी की जांच में यह पाया गया कि स्टोन क्रशर 1.11.2011 तक पांच हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र मे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। जोकि पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 और EIA अधिसूचना 2006 के प्रावधानों का सीधा उल्लघंन है। जांच रिपोर्ट में इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 56 P NO 19628/2009 दिनांक 27.2.12 को दिये गये फैसले का भी उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण नियमों का उल्लघंन इन क्रशरो ने न केवल पर्यावरण को ही नुकसान पंहुचाया है। बल्कि अवैध रूप से करोड़ो का कालाधन भी अर्जित किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के शिमला कार्यालय ने इस पर विस्तृत

शेष पृष्ठ 8 पर..............................

विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियां उचित नहीं :राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान नई उंचाईयों को छू सकता है बशर्ते इससे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति दृढ़ ईच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे तथा ईमानदारी से कार्य करने के साथ-साथ जिम्मेवारी एवं जवाबदेही को भी सांझा करे।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 27वीं वार्षिक कोर्ट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन एवं मानवीय विकास के केन्द्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक गतिविधियां इन संस्थानों में शैक्षिक माहौल को दूषित कर रही हैं और विश्वविद्यालय में हड़ताल व धरने प्रदर्शनों से संस्थान की गरिमा पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों के संस्थान हैं और इनमें बुद्धिमता एवं अध्ययन की छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेवार लोगों को समस्या के बारे में सोचना चाहिए और संस्थान की बेहतरी के लिए इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा युवाओं को सही मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेवारी है और शिक्षण संस्थान में वातावरण में सुधार लाने के लिए उनके रचनात्मक सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्यों में से विधायक अनिरूद्ध सिंह को सर्व सम्मत्ति से कार्यकारिणी परिषद में चुना गया।

हि.प्र. दंत महाविद्यालय शिमला के मौजूदा प्राचार्य एवं दंत विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डा. आर.पी. लुथरा को भी सर्वसम्मति से भारतीय दंत परिषद का सदस्य चुना गया।

विश्वविद्यालय कोर्ट ने राज्य विधानपालिका के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2013-14 व 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदनों को भी मंजूरी प्रदान की। विश्वविद्यालय कोर्ट ने वर्ष 2001-12 के लिए वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की।

इससे पूर्व कुलपति प्रो. ए. डी. एन. बाजपेयी ने कहा कि हि.प्र. विश्वविद्यालय ने गत पांच वर्षो के दौरान अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं और विश्वविद्यालय के स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिसर में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में एससीए के लिए सीधे चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाया है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विभाग के लिए मापदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है जिनकी निर्धारित समयावधि में समीक्षा की जाएगी। शिमला के समीप घणाहट्टी में विश्वविद्यालय के नये परिसर के निर्माण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके लिए 120 बीघा भूमि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कुलाधिपति का आभार जताया और उन्हें आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए सभी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुल सचिव डा. पंकज ललित ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. राजिन्द्र सिंह चौहान अन्य कोर्ट सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
TENDER

Sealed item rate tender on the form No. 6&8 are invited by the Executive Engineer Nalagarh Division HPPWD Nalagrah on behalf of the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative. PWD in the appropriate class for the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative.

(1) The Last Date & Time of receipt of Application for tender from 26.10.2016 12:00A.M.
(2) The Last date of issue of tender form 26.10.2016 12:00 A.M upt o 4:00 P.M.
(3) The Last receipt of tender 27.10.2016 10:30 A.M.
(4) The date of opening of tender 27.10.2016 at 11:00 A.M.

Earnest Money in the Shape of National Saving Certificate/ Time Deposit accounts/saving accounts in any of the Post Office/ Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN HPPWD Nalagrah must be accompanied with the tender documents. The conditional tender and the tender received Without earnest money will be summarily rejected, The Executive Engineer reserves right to accept or rejected any or all tenders, the tenders shall be kept open for 120 days.

The contractor should be registered as dealer under HP sale Tax Act 1968 and also produce sale tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time Limit
1. Annual maintenance /Periodical Rapair of Link road to Brahman Majra K.M. 0/0 to 1/500 (SH:- P/L Premix carpet with seal coat in km 0/0 to 1/0)	5,91,901-/	11800/-	Two Months	350/-
2. Construction of shardighat Chassi Diggal road k.m. 5/0 to 10/500 (SH:- C/O B/wall at Rd 7/140 to 7/180)	1,60,661/-	3300/-	Two Months	350/-
3. A/R & M/O Ramshehar Suna Nerli road k.m. 0/0 to 25/070 (SH:- P/L W.B.M. G-III and 2cm thick premix carpet with seal coat in km 1/0 to 6/0	4,92,660/-	10,000/-	Two Months	350/-
4. Special Repair and additional alteration to spram station at Adhuwal in Tehsil Nalagarh (SH:- C/O Shed Over generator set and Submersible Pump	1,47,322/-	3000/-	One Month	350/-
5. C/O rain shelter on Ramshehar suna Nerli raod at sai Charog Rd 22/260	1,03,497/-	2100/-	One Month	350/-

Adv. No.- 2483/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

वन निगम अपनी गतिविधियों में विविधता लाये : भरमौरी

शिमला/शैल। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि वन निगम को अपनी गतिविधियों में विविधता लाकर अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम को राज्य में 37 इको टूरिज्म स्थल स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश जारी किए गए हैं।

भरमौरी हि. प्र. राज्य वन निगम के निदेशकमण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों जैसे उत्तरांचल के म डल के अध्ययन के निर्देश दिए ताकि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार उनको अपनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की दिशा में निगम को पौधरोपण के लिए भी आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय हरित उच्च मार्ग मिशन के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्गो के किनारों पर पौधे रोपने चाहिए। मंत्री ने निगम की फैक्ट्रियों में नवीनतम उपकरण स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे बाजार की स्पर्धा में टिक सकें। निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, प्रधान सचिव वन तरूण कपूर, मुख्य अरण्यपाल वन डा. एस.पी. वासुदेवा, निगम के प्रबन्धक निदेशक सी.एस. सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल का राज्य में जैविक खेती पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सिक्किम की तर्ज पर जैविक कृषि राज्य के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसका शुभारंभ चंबा जिले के पांगी क्षेत्र से किया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्यपाल चंबा जिले के किलाड़ के कला मंच में भूमि स्वच्छता जागरूकता अभियान चरण-1 के अंतर्गत शून्य बजट जैविक कृषि संबंधित कार्यशाला एवं संकल्प दिवस के शुभारंभ अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में पांगी घाटी की 16 पंचायतों के किसानों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पांगी क्षेत्र के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी यहां रहकर खेती-बाड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए राज्य से बाहर बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां यहां के किसान अपने उत्पादों को 'पांगी उत्पाद' के नाम से बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि हर मायने में फायदेमंद है। इससे जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, वहीं पानी की खपत भी कम होती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इस खेती को अपनाकर किसान को बाजार से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके उत्पाद फायदेमंद हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शीघ्र ही इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे और पांगी घाटी में जैविक कृषि को लेकर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के विख्यात वैज्ञानिक व पदमश्री पुरस्कार प्राप्त डा. सुभाष पालेकर को आमंत्रित कर किसानों को शून्य लागत कृषि के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कृषि को अपनाने के लिए किसानों को देसी नस्ल की गाय पालनी होगी जिसका गोबर व गौमूत्र खेतों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग पचास लाख लोगों ने शून्य लागत कृषि को अपनाया है। एक देसी गाय के सहयोग से लगभग तीस एकड़ जमीन पर खेती की जा सकती है।

उन्होंने लोगों से बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ संस्कारवान व उच्च नैतिक मूल्य देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा तथा कन्या शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सभा के प्रयासों की सराहना की तथा किसानों को जैविक खेती संकल्प पत्र पढ़कर शपथ दिलाई। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।

पर्वतीय कृषि जन कल्याण एवं विकास सहकारी सभा भंजराड़ू के मुख्य सलाहकार ओपी शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए पांगी घाटी पहुंचने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभा की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में यह संस्था प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पुष्प उत्पादन, सेब के रूट स्टॉक स्टेशन, पॉलीहाउस नर्सरी इत्यादि के अलावा क्षेत्र में जैविक कृषि व बागवानी को प्रोत्साहन दे रही है। सभा द्वारा किसानों को इस बारे में प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जा रहा है।

सभा ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस ज्ञापन में क्षेत्र के 4000 लोगों ने हस्ताक्षर कर किलाड़ से सुरंग निर्माण का आग्रह किया गया है ताकि यह क्षेत्र 12 महीने शेष विश्व से जुड़ा रहे। अत्यधिक बर्फबारी के कारण सर्दियों में यह क्षेत्र शेष विश्व से कट जाता है।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में युद्ध स्मारक कार्य का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक के समीप निर्माणाधीन युद्ध संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता ने मुख्यमंत्री को किए जा रहे निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विशेषकर, पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के उपरांत अभूतपूर्व विकास किया है, और हिमाचल प्रदेश आज देश भर में विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहा है और वह नकारात्मक गतिविधियों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय परिधि गृह में जन शिकायतें भी सुनी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महात्मा गांधी को उनके 147वीं जयंती पर प्रदेश के लोगों की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें

श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी उनके साथ थे।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के सपने के साथ गांधी जी ने हमें अहिंसा और सह-अस्तित्व का संदेश दिया। उनके लिए स्वच्छता स्वास्थ्य व अरोग्य का मंत्र था जो कि ईश्वर के उपरांत उनके हृदय के सबसे नजदीक था। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत के प्रति अपनी वचनबद्धता को आग्रह किया ताकि महात्मा गांधी के स्वपन को साकार किया जा सके। महात्मा व बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी एक महान आत्मा होने के साथ अतरराष्ट्रीय शांति-दूत थे। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वच्छ भारत की शपथ भी दिलाई। उन्होंने हिमाचल को हरित व स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता शपथ पर हस्ताक्षर भी किए।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 112वीं जयंती के अवसर पर सीटीओ पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पूष्पाजंलि अर्पित की तथा कहा कि शास्त्री जी एक सच्चे राष्ट्रवादी व और भारतीय राजनीति के एक महान नेता थे जिनकी हमारे जीवन पर अमिट छाप है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा 'जय जवान जय किसान' आज के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा कि ताशकंद में भारत पाक युद्ध के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री का निधन देश के लिए भारी क्षति थी तथा यह दुखद घटना ताशकंद में दो देशों के बीच शांति की घोषणा के उपरांत घटित हुई। उन्होंने कहा कि देश उनकी सेवाओं को हमेशा याद करता रहेगा।

इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी रिज मैदान पर एकत्रित हुए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा गाए गए गीतों से वातावरण देश भक्तिमय हो उठा। जिला ग्रामीण कांग्रेस समिति के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, विधायक रवि ठाकुर, महापौर संजय चौहान, कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष मंगलेट, हिमालच प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, उप महापौर टिकेन्द्र सिंह पंवर, पार्षदगण, उपायुक्त रोहण ठाकुर, पुलिस अधीक्षक डी.डब्ल्यू नेगी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी व शहर के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने गांधी जयंती पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जागरूकता लाने पर बल दिया ताकि स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज

के दिन दो महापुरूषों की जयंती मनाई जा रही है। इन दोनों ओजस्वी नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। राज्यपाल ने रोटरी क्लब शिमला, मिड टाऊन द्वारा शिमला के नजदीक घणाहटटी में आयोजित निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर तथा स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ करने के उपरांत कहा रोटरी क्लब का न केवल देश में बल्कि विश्व में विस्तृत इतिहास है। क्लब का हमेशा ही समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है और क्लब हमेशा ही मानवता के कल्याण के लिए प्रयासरत रहा है। उन्होंने कहा कि रोटरी के सदस्य हमेशा ही सामाजिक कार्य को निस्वार्थ भावना से एक मिशन के रूप में लेते हैं। राज्यपाल ने घणाहटी स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया।

सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:भरमौरी

शिमला/शैल। सड़क,शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शुमार है तथा जन जातिय क्षेत्रों में तीव्र गति से विकासात्मक कार्यो को अमली ज़ामा पहनाया जा रहा है। यह शब्द वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने करयोणी पंचायत में 80 लाख की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करयोणी के अतिरिक्त भवन की आधारशीला रखने के उपरांत स्थानीय लोगों को सम्बोधित करते हुए कहे। इससे पूर्व उन्होंने साच पंचायत में 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कार पार्किंग व राजकीय प्रथमिक पाठशाला मलोथ चौसर के भवन की भी आधारशीला रखी। वन मंत्री ने साच पंचायत में लोगों की जन समस्याएं सुनते हुए कहा कि साच गांव में भू-स्खलन को रोकने हेतु वन विभाग व स्थानीय लोगों के सहयोग से पौधारोपण के कार्य किए जाएंगे।

वन मंत्री ने रविवार को शौर गांव में राजकीय उच्च विद्यालय शौर के 79 लाख रुपये से निर्मित होने वाले अतिरिक्त चार कमरों के भवन का भी शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अजोग पुल के जीर्णोद्धार पर 16 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे तथा सम्बन्धित विभाग को जल्दी कार्य आरम्भ करने के आदेश दिए।

सिचु पंचायत में उन्होंने स्तरोन्नत पशु चिकित्सालय का भी शुभारम्भ किया। सिचु पंचायत में 70 लाख रुपये से बनने वाले वन्य प्राणी रेंज ऑफिस के आवासीय भवन की भी आधारशीला रखी। वहां उन्होंने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुर्छ गांव को भी वन्य प्राणी अभयरण्य क्षेत्र से बाहर रखने के लिए मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा।

हिमाचल पुनः बना राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य

शिमला/शैल। स्वच्छता अभियान और अम्रुत मिशन में मिले राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के विकास के इतिहास में उस समय एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया जब इसे नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान मिशन और अम्रुत मिशन को लागू करने में राष्ट्र स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिले। मण्डी जिला को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत खुला

शौच मुक्त जिला घोषित होने के कारण और शिमला को अम्रुत मिशन में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार मिले।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मण्डी जिला के आयुक्त संदीप कादम तथा बल्ह क्षेत्र की खण्ड विकास अधिकारी वसुन्धरा सूद को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक दिवसीय इंडो-सेन (INDO-SAN 2016) सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया, जबकि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को शिमला व कुल्लू जिला में अम्रुत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्रियता से कार्य करने और ई-गवर्नैंस व अन्य अनेक क्षेत्रों में अनुकरणीय पहल करने के लिए पुरस्कृत किया। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, शहरी विकास विभाग के शहरी निदेशक डा.आर.के. प्रूथी तथा नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय व अन्य उच्च अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इंडो-सेन 2016 के इस एक दिवसीय राष्ट्र-स्तरीय सम्मेलन में भाग लेते हुए, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विकास की नई उचाइयां छू रहा है तथा कहा कि आज राष्ट्र स्तर पर प्रदेश को जो यह पुरस्कार मिले हैं इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रदेशवासियों को जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने में सदैव अग्रणी रहा है तथा भरोसा दिलाया कि आगे भी प्रदेश अम्रुत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में अग्रणी रहेगा। उन्होंने सराहनीय कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के प्रयासों की सराहना करने पर उनका आभार व्यक्त किया।

अम्रुत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि इससे प्रदेश को वर्ष 2015-16 के लिए 3.54 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी जिससे इन जिलों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने प्रदेश को राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की विकास के प्रति सक्रिय भागीदारी को देखते हुए इस प्रदेश के और जिलों को भी इन योजनाओं के तहत लाया जाए ताकि प्रदेश में विकास की निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी जिला को खुला शौच मुक्त करने के लिए राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए जिला के अधिकारी, कर्मचारी तथा समस्त जिलावासी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विकास में भागीदारी का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार को आश्वस्त किया कि यह प्रदेश पंचायती राज व ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करने में सदैव अग्रणी रहेगा।

पानी की टंकियों की सुरक्षा एवं सफाई सुनिश्चित बनाई जाए:स्टोक्स

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कक्कड़हटी में पानी की टंकियों को दूषित करने की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए यहां सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई।

पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने मंत्री को अवगत करवाया कि इस घटना की प्राथमिक सूचना दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच की जा रही है। मुख्य अभियन्ता आर.एम. मुकुल ने मंत्री को अवगत करवाया कि सफाई के चलते 28 सितम्बर, 2016 को पानी की टंकी खाली थी और इससे पानी की आपूर्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने स्कूल की टंकियों का निरीक्षण करने के साथ-साथ निकटतम गांव को की जाने वाली जलापूर्ति के टैंक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक इस टैंक से होने वाली जलापूर्ति रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि अर्की के अधिशासी अभियन्ता ने भी स्थानीय पंचायत प्रधान को साथ लेकर जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया और कनिष्ठ अभियन्ता को पानी के नमूनों की जांच के उपरांत एक रिपोर्ट देने को कहा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को पेयजल टैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए और कहा कि इस तरह की घटनाएं जो लोगों की जान के लिए खतरा बने, भविष्य में न हों। उन्होंने अधिकारियों से टैंकों की नियमित सफाई एवं पेयजल गुणवत्ता बनाए रखने तथा टैंकों में तालाबंदी को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जा रही है।

मंत्री ने पुलिस विभाग को मामले की तेजी से जांच करने तथा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को शीघ्र पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

मुर्ख लोगो से वाद-विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते है।........ चाणक्य

सम्पादकीय

और मोदी ने कर दिखाया

उरी और पठानकोट के आतंकी हमलों का पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंक के ट्रेनिंग पर हमला करके जिस तरह का जबाव पाकिस्तान को दिया गया है उसके लिये प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र है। क्योंकि एक देश के लम्बे अरसे से आतंकी गतिविधियों का शिकार होता आ रहा था जिसके पठानकोट और उरी ताजा उदाहरण थे। सैंकड़ों लोग इस आतंक का शिकार होकर अपने प्राण गंवा चुके है। देश के दो प्रधानमंत्री एक मुख्य मन्त्री और संसद तक आतंक का शिकार हो चुके है। हर आतंकी घटना के पीछे सीमा पार से समर्थन और साजिश दोनों के प्रमाणिक सबूत मिलते रहे है। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इन सबूतों को मानने से इन्कार किया। विश्व समुदाय भी आतंक की निन्दा करने से अधिक कुछ नही कर पाया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनों की सूची लगातार पाकिस्तान को दी जाती रही लेकिन इसका असर उस पर नहीं हुआ। उसके समर्थन और सरंक्षण में आतंक की फौज लगातार बढ़ती रही उसके लिये बाकायदा ट्रेनिंग कैंप संचालित होते रहे। भारत भी सबूत सौंपने और माकूल जबाव देने के ब्यानो से आगे नही बढ़ा। देश का राजनीतिक नेतृत्व इस तरह की कारवाई करने का फैसला नहीं ले पाया। जबकि इस तरह का फैसला लेना लगातार बाध्यता बनता जा रहा है।

ऐसा फैसला लेने से पहले अपने पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान की इस हकीकत का खुलासा रखा जाना आवश्यक था। इसके लिये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से विदेश यात्राओं की रणनीति अपनाई और उसकी शुरूआत सार्क देशों से की उसके परिणाम आज सार्क सम्मेलन के स्थगित होने की नौबत तक पहुंचने से सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान को मोदी ने सफलता पूर्वक सार्क देशों में ही अगल थलग कर दिया है यह उनकी कूटनीतिक सफलता है। पाक अधिकृत कश्मीर में हुई सर्जिकल कारवाई में आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के दो सैनिक भी मारे गये है। लेकिन पाक इस कारवाई को स्वीकार भी नही कर पा रहा है क्योंकि यह कारवाई आतंकी कैंपो पर हुई है यदि पाक इसे स्वीकार कर लेता है तो इसका अर्थ होगा कि उसने उसके यहां आतंक ट्रेनिंग कैंपों का होना स्वीकार कर लिया है और इस स्वीकार के साथ ही वह विश्व समुदाय के सामने बेनकाब हो जाता है क्योंकि वह ऐसे कैंपो के होने से ही इन्कार करता आया है। जब पाकिस्तान ने इन कैंपो को आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट करने का काम किया था तो संभवत: उसकी नीति यह रही होगी कि यदि भारत की ओर से कोई सैनिक कारवाई होती है तो उसमें आम नागरिकों को भी हानि पंहुचेगी और वह भारत को विश्व समुदाय के सामने एक आक्रामक करार दे पायेगा। लेकिन किसी भी नागरिक को कोई नुकसान न होने से भारत इस संभावित आक्षेप से बच गया। यही कारण है कि पाक इस कारवाई को स्वीकार नही कर पा रहा है।

अब जहां मोदी इसके लिये समर्थन और बधाई के पात्र हैं वहीं पर उनसे यह भी उम्मीद है कि भारत जिन आतंकी सरगनाओं की पाक से मांग करता आ रहा है आज उन लोगों के खिलाफ भी इसी स्तर की कारवाई हो जानी चाहिये। जिस हाफिज सईद, अजहर मसूद और दाऊद इब्राहिम की तलाश भारत को है और वह पाकिस्तान में बैठे हुए हैं पाक उनको आतंकी नही मानता। उनके पाक में होने से भी इन्कार करता है। उनके खिलाफ आज इसी तरह की कारवाई की आवश्यकता है। आज पूरे देश का मनोबल इस पर बना हुआ है। फिर जब तक आतंक का संचालन करने वाले यह लोग बैठे है और उनको वहां की सरकार का समर्थन हासिल है तब तक आतंकी साजिशों की संभावना बराबर बनी रहेगी। ऐसी संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिये ऐसी ही सर्जिकल कारवाई की आवश्यकता है। फिर जब अमेरिका लादेन के लिये ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। ऐसी कारवाई की अपेक्षा अब मोदी से की जाने लगी है और उन पर देश को भरोसा भी अब होने लगा है।

प्रदेश सरकार अब तक 378 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को नौकरी दे चुकी है

प्रदेश सरकार राज्य में युवा सेवाओं एवं खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्प है ताकि युवाओं की ऊर्जा का राष्ट्र-निर्माण तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक सदुपयोग किया जा सके। सरकार द्वारा युवा खेलों व उनकी सेवाओं को सही दिशा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश में बहुद्देशीय अन्तरंग खेल परिसरों, खेल मैदानों व अन्य ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तथा राज्य युवा बोर्ड को एक करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत युवा हैं, जिन्हें आत्म-अभिव्यक्ति और आत्म-विकास के लिए समुचित अवसरों की दरकार है। प्रदेश में युवा गतिविधियों को बल देने के लिए युवा क्लबों के वार्षिक अनुदान को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। राज्य में युवा सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए नोडल युवा क्लबों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में युवा गतिविधियों एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न खेल संघों को मिलने वाली अनुदान राशि में समुचित बढ़ौतरी की गई है। राज्य स्तर के खेल संघों को वर्ग-ए में मिलने वाली एक लाख रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये, वर्ग-बी में 75,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा वर्ग-सी में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से जिला खेल संघों को वर्ग-ए में 10,000 से 15,000 रुपये, वर्ग-बी में 8,000 से 12,000 रुपये तथा वर्ग-सी में 5,000 से 8,000 रुपये की बढ़ौतरी अनुदान राशि में की गई है।

इसी प्रकार से इस वर्ष बी-वर्ग में किसी भी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 80,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये, द्वितीय को 40,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये व तृतीय को 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये जबकि इसी के तहत टीम स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 16,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति खिलाड़ी, द्वितीय को 8,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति खिलाड़ी किया गया है। इस स्पर्धा के तहत पहले तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को कोई नकद

खेल पुरस्कारों की राशि में सम्मानजनक बढ़ौतरी

पुरस्कार नहीं दिया जाता था जबकि सरकार द्वारा इस वर्ष तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 15,000 नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा ऑलोंपिक खेलों में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने पर क्रमश: 2 करोड़, एक करोड़ व 50 लाख रुपये जबकि कॉमनवैल्थ व एशियन खेलों में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने पर क्रमश: 20 लाख, 10 लाख व 6 लाख रुपये के नकद पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है।

इस के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष किसी भी अखिल भारतीय इंटर-विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी राष्ट्रीय स्कूल खेल की वयक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी कनिष्ठ व उप-कनिष्ठ की राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा तथा विभागीय राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को मिलने वाले नकद पुरस्कारों में समुचित वृद्धि की गई है।

सरकार द्वारा किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया अन्तर्राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 8 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर इस वर्ष 10 लाख रुपये जबकि कॉमनवैल्थ व एशियन खेलों में किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 6 लाख के नकद पुरस्कार को भी बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 2 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 5 लाख रुपये

जबकि अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी खेल स्पर्धा में भारतीय टीम के सदस्य के रुप में सम्मिलित होने के लिए मिलने वाली 80,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर इस वर्ष एक लाख रुपये किया गया है। गत तीन वर्षों में विभिन्न खेलों में उम्दा प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश के 223 खिलाड़ियों को 1.9 करोड़ रुपये की राशि नकद पुरस्कारों के रुप में प्रदान की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वर्ष राज्य परशुराम पुरस्कार की राशि को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। इस पुरस्कार के तहत अभी तक मण्डी की सुमन रावत मैहता को एथेलैटिक्स, शिमला के चमन सिंह धौटा को बालीवाल, शिमला के ही वरिन्द्र शर्मा को बॉक्सिंग, काजा के सकालजंग दोरजे को तीरअंदाजी, बिलासपुर की कमलेश कुमारी को एथेलैटिक्स, कुल्लू की उमा कुमारी को स्कींइग, शिमला के भक्त सिंह ठाकुर को बॉक्सिंग, चम्बा के राजीव नायर को क्रिकेट, चन्द्रेश्वर शर्मा को बॉक्सिंग, कुल्लू के चुनी लाल को स्कींइग, मण्डी के शिव चौधरी को बॉक्सिंग, शिमला के अमन सैणी को बॉक्सिंग, हमीरपुर की नूतन कुमारी को जूडो, हमीरपुर की ही पुष्पा ठाकुर को एथेलैटिक्स, कुल्लू की संजो देवी को एथेलैटिक्स, सिरमौर की प्रियंका नेगी को कब्बडी, कांगड़ा की सोनिया राय को शूटिंग, मण्डी के जौनी चौधरी को कुश्ती, मण्डी के ही संजय कुमार यादव को बुशु, कुल्लू की भूवनेश्वरी को विंटर गेम्ज, शिमला की रानू देवी को कब्बडी तथा बिलासपुर की पूजा ठाकुर को कब्बडी सहित अब तक प्रदेश के कुल 22 होनहार खिलाड़ियों को राज्य परशुराम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसके चलते अभी तक प्रदेश के 378 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जा चुकी है।

वैश्विक जीवन एवं निरंतरता, एक गांधीवादी दृष्टिकोण

डी जॉन चेल्लादुरै

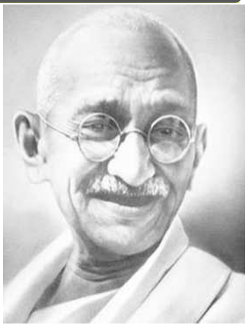

आधुनिकीकरण ने एक व्यक्ति के सामर्थ्य को वैश्विक रूप प्रदान किया है। उपग्रह संचार, वायु मार्गों एवं भारी जमीनी उपकरणों के साथ अब हमारी शक्ति और क्षमता वैश्विक हो गई है। अल्फ्रेड नार्थ वाइटहेड के शब्दों में आज का व्यक्ति जो भी बना है उसमें सम्पूर्ण दुनिया का उदय और सम्मिलन शामिल है। मानव जीवन ने विश्वरूप हासिल कर लिया है।

वैश्विक जीवन ने कई चुनौतियां को भी जन्म दिया है। अपने दैनिक जीवन में हम आत्मकेंद्रित व्यवहार से लेकर पर्यावरणीय क्षति जैसी आचार सम्बन्धी उल्लंघनों का नित दर्शन करते हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की चाह में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम शिष्ट समाज के एक जोखिम भरे पथ पर चले जा रहे हैं।

यूरोप में आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक खतरों के शुरुआती दुष्परिणाम को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने और मानव सभ्यता पर इसके दुष्प्रभाव को देखने के बाद गांधीजी ने एक वैकल्पिक जीवनशैली की प्रस्तावना की। यह भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन का एक सुन्दर सम्मिश्रण था, जैसा कि गांधीजी कहते थे, शब्दों, विचारों और कर्म में समन्वय होना। जे सी कुमारप्पा ने इसे यथोचित जीवनशैली कहा।

पारिस्थितिक उपयुक्तताओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैव एवं पारिस्थितिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह जीवन जीने की अनुकूलतम जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ सबकुछ एक अनुकूल अनुपात में करना, न ज्यादा न कम। यह किसी भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है तथा यह प्रकृति से अधिक सामंजस्यपूर्ण है।

इस अनुकूलता के सिद्धांत को आप उनकी जीवन पद्धति के सभी पहलुओं को परिभाषित करते देख सकते हैं चाहे वह निजी जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन हो अथवा शारीरिक या आध्यात्मिक जीवन ही क्यों न हो। उदाहरण के लिया गांधी जी ने सिर्फ उपयुक्त एवं अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रतिपादन किया, यह इतनी पुरानी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी काम की न रहे और न ही इतनी परिष्कृत की उपयोगकर्ता को अचंभित कर दे। उन्होंने कहा की सिलाई मशीन इसी तरह की एक उपयुक्त मशीन है। यह उपयोगकर्ता को हाथ से सिलाई के परिश्रम से बचाती है साथ ही यह इतनी अधिक मात्र में उत्पादन नहीं करती की बेरोजगारी उत्पन्न हो तथा न ही यह बिजली का उपयोग करती है और न ही कोई प्रदूषण।

किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार एक मापा जा सकने वाला संसाधन है। पुंज या थोक उत्पादन कुछ को वैश्विक हिस्से में से औसत से अधिक लेने की अनुमति देता है जिसकी वजह से काफी बढ़ी संख्या में लोगों को औसत से कम प्राप्त होता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अवसर अन्तराल उत्पन्न होता है जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। विश्वव्यापी निर्माण और उत्पादन संगुटिकाओं के स्थान पर विकेन्द्रित ग्रामीण उद्योगों का उन्होंने प्रतिपादन किया ताकि उत्पादन संभावनाओं और रोजगार आवश्यकताओं का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। जे सी कुमारप्पा के शब्दों में उन्होंने टिकाऊ अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। उचित उपकरण के साथ भूमि पर रोटी श्रम, ऐसा जीवन जीने के लायक होता है, गांधीजी ने रस्किन बांड के इन विचारों का भी अनुमोदन किया क्योंकि यह अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों को ही उचित न्याय देता है।

गरीबी और वैभव दो चरम सीमायें हैं। गांधीजी के अनुकूलतम दृष्टिकोण की विशिष्टता यह है कि गरीबी को हटाने पर काम करते वक्त (उनके 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक) उन्होंने समान रूप से ही स्वैच्छिक गरीबी जिन के पास आवश्यकता से अधिक है, पर भी उतना ही जोर दिया है। गांधीजी के अनुसार स्वैच्छिक गरीबी के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक व्यवस्था 'ट्रस्टीशिप' की थी। उन्होंने जमनालाल बजाज से कहा कि वे अपने धन के ट्रस्टी बन जाए और इसे लाखों गरीब लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दें।

गांधी के अहिंसक उचित आर्थिक विचारों से संकेत लेते हुए ब्रिटिश अर्थशास्त्री ई एफ शूमाकर ने लिखा, "लघु उत्तम है: अर्थशास्त्र का एक ऐसा अध्ययन जिसमें लोग अहम् हैं"। क्लब ऑफ रोम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक संघ है उसने 'सीमित संसाधनों के साथ चरघातां की आर्थिक एवं जनसंख्या वृद्धि के कंप्यूटर सिमुलेशन' पर आधारित अध्ययन से एक रिपोर्ट सन्निखित की। उन सभी ने स्वयं संयमित उपयुक्त जीवनशैली का समर्थन किया।

पारिस्थितिकी ऋण दिवस एक कैलंडर में वह स्थान चिन्हित करता है जिसके पश्चात् मानव द्वारा किये गए प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को प्रकृति उस वर्ष पुन: प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि यह उपभोग संवहनीय दर से होता है तो यह दिवस वर्ष के अंत में आना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि मनुष्य 365 दिनों के प्रावधान को मात्र 225 दिनों में ही समाप्त कर लेता है। मानवता जिस प्रकार से अपनी वार्षिक संसाधनों को हर 13 अगस्त तक समाप्त कर लेती है, उस वजह से गांधीजी ने जो कहा था वह एक तरह से भविष्यवाणी ही प्रतीत होती है: 'पृथ्वी पर हर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के संसाधन तो हैं किन्तु सबकी लालसा पूर्ण करने के लिए नहीं' 'आवश्यकता से अधिक उपभोग एक प्रकार से चोरी करने के बराबर है', जोकि प्रकृति के प्रति एक हिंसा के सामान है। हो सकता है कि 'लालसा की पूर्ति' के स्थान पर यदि 'आवश्यकताओं की पूर्ति' की जाये तो शायद हम पारिस्थितिकी ऋण दिवस को कुछ पीछे कर सकें।

ग्राम राज्य की जो अवधारणा गांधीजी ने प्रतिपादित की थी वह एक अनुकूलतम समाज को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक जुड़ाव (सहयोग और आपसी सहायता) की आवश्यकता होती है परन्तु इसका परिमाण किस हद तक बढ़ाया जा सकता है इसकी एक बहुत ही छोटी सीमा होती है। एक स्वस्थ समाज वह है जिसमें कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अन्य जनों तक पहुँच सकता है। उन्होंने समुद्रीय परिमंडल के जैसे एक सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की जिसके केंद्र में व्यक्ति होगा फिर क्रमश: परिवार, गाँव, जिला, राज्य, देश एवं दुनिया होगी।

वैश्विक जीवन ने विविध मनुष्यों के एक साथ मिलकर रहने को जन्म दिया। विभिन्न धर्मों, जातीय और सांस्कृतिक उन्मुखीकरण के लोग हर इलाके में रहने के लिए आ गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने भू दूरी वैसे भी खत्म दिया है। स्वयं की धार्मिक-सांस्कृतिक संबद्धता और सामाजिक विविधता के मद्देनजर एक अनुरूपित आचरण के लिए हमें एक मध्यवर्ती व्यवहार स्वरुप को अपनाने की जरूरत है। गांधीजी के ग्यारह व्रतों में से एक 'सर्वधर्म सम्भाव' इस सद्गुण के महत्व को बताता है खासकर जो वैश्विक लोग हैं उनके लिए। ई स्टेनली जोन्स जोकि एक अमेरिकी मेथोडिस्ट पुजारी थे उन्होंने जब गांधीजी से पूछा, मसीह कहते हैं 'अपने पड़ोसी से प्रेम करो', आप अहिंसा को इससे बेहतर क्या संदेश दे सकते हैं? गांधीजी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि 'मेरा कोई शत्रु नहीं है'। उन्होंने कहा 'गुनाह और गुनाहकर्ता दोनों एक नहीं हैं'। मैं 'गुनाह' के खिलाफ हूँ, गुनाहकर्ता तो मेरा ही व्यक्ति है। शत्रु से प्यार करने की तुलना में, दूसरों में 'दुश्मन' को खोजने की आदत पर काबू पाना अधिक महत्वपूर्ण है।

विस्तृत मानव व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दो अलग अलग अंतिम सिरे हैं जिसमें पूर्ण हिंसा एक सिरे पर है तो नैतिकतावादी अहिंसा दूसरे सिरे पर। हालांकि गांधीजी अहिंसा के समर्थक थे किन्तु इसकी चरम अभिव्यक्ति की जगह उन्होंने इसके व्यवहारिक स्वरुप तक ही अपने को सीमित रखा। इसीलिए उन्हें कुछ अपरिहार्य प्रकार की हिंसा भी स्वीकार थी जैसे फसलों को नष्ट करने वाले जानवरों को दूर भगाना।

गांधीजी ने अपने इष्टतम दृष्टिकोण को स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी प्रयुक्त किया। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषित कर दिया है कि, 'मोटापा' एक वैश्विक महामारी है और जीवन शैली से उत्पन्न सभी खतरों का एकमात्र स्रोत है। गांधीजी ने तर्क दिया, 'असाधारण शरीर वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि स्वस्थ ही है। गांधीजी का कहना है कि संभवत: उसने अपनी यह मांसपेशियां कोई अन्य मूल्य देकर अर्जित की हैं। अपनी पुस्तक स्वास्थ्य की कुंजी में उन्होंने सिर्फ पर्याप्त पौष्टिक भोजन, सक्रिय भौतिक जीवन, अच्छी नींद और स्वस्थ सोच द्वारा एक संतुलित जीवन का प्रस्ताव रखा था। उनका पर्यावरण के अनुकूल शौचालय का डिजाइन अपने समय में सर्वश्रेष्ठ था और इसे 'वर्धा शौचालय म डल' कहा जाता था।

पृथ्वी इस समय इस पर मौजूद एवं भविष्य में आने वाले सभी जीवों की धरोहर है। एक भव्य जीवन की हमारी होड़ में, अगर हम इस पृथ्वी को एक उपभोगित, समाप्त प्राय रूप में पहुंचा दें तो, शायद हम प्रकृति के खिलाफ एक घोर अन्याय कर रहे हैं। गांधीजी के जीवनशैली के अहिंसक तरीके और इसके उचित उपकरण, विकेन्द्रित सामाजिक व्यवस्था के साथ सक्षम अर्थव्यवस्था जो एक व्यक्ति को अपने पारिस्थितिकी तंत्र के सहजीवी होने में सक्षम करती है, आज हमारे लिए और अधिक प्रासंगिक सीख लगती है।

आत्मा, विवेक और स्वच्छ भारत!

स्वच्छ भारत विश्व के लिए भारत द्वारा दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य है

एम. वेंकैया नायडू

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के साईखेड़ा गांव की रहने वाली संगीता अहवाले ने अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। छत्तीसगढ़ जिले के धमतारी जिले में स्थित कोटाभरी गांव की 104 वर्ष आयु की वृद्धा कुंवर बाई ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपनी बकरियां बेच दीं। कोलारस ब्लॉक के गोपालपुरा गांव की आदिवासी नववधू प्रियंका अपनी ससुराल के घर में शौचालय न होने के कारण अपने माता-पिता के घर लौट आई। आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले की एक मुस्लिम महिला ने अपनी नई पुत्रवधू को एक शौचालय उपहार में दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लड़कियों ने ऐसे घरों में शादी करने से मना कर दिया जहां शौचालय नहीं बने थे। इन सभी मामलों में महिलाएं ही आत्म सम्मान को कायम रखने के लिए नई भावना को जागृत करने में आगे रही हैं। स्कूल की छात्र लावण्या तब तक भूख हड़ताल पर बैठी रही जब तक कर्नाटक स्थित उनके गांव हालनहल्ली के सभी 80 परिवारों में शौचालयों का निर्माण नहीं हो गया। स्वच्छ भारत की दिशा में आए बदलाव के इस भारी परिवर्तन की ये कुछ झलकियां ही हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई अग्रणीय पहलों में से एक है। निश्चित रूप से देश को स्वच्छ बनाने का यह विचार बिलकुल नया नहीं है। इससे पहले भी संपूर्ण स्वच्छता मिशन और निर्मल भारत अभियान जैसे इसी प्रकार के प्रयास किये गये हैं, लेकिन इस बार इसमें इरादे और कार्यान्वयन की शक्ति के अंतर का है। इस बार व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो शौचालयों के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। शौचालय बना लेना आसान है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों को उन्हें उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाए।

यह उल्लेखनीय है कि आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में बोलते हुए देश में सफाई की खराब स्थिति के बारे में अपनी आवाज उठाई थी। काशी में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली सभी सड़कों को देखकर वे स्तंभित रह गए थे। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता, राजनीतिक आजादी जितनी ही महत्वपूर्ण है। भारत को औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए 69 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह देश खुले स्थानों में चारों और फैली गंदगी के अभिशाप से आजाद नहीं हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 तक देश को इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। युगों-युगों से भारतीय संस्कृति और लोकाचार में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया है। व्यक्तिगत मुक्ति के एक साधन के रूप में आत्मा की पवित्रता की अवधारणा वास्तव में प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के साथ-साथ वैचारिक प्रक्रियाओं और कार्यों के सभी पहलुओं से जुड़ी है। चारों और फैले कचरे के ढेर, खुले में कूड़ा करकट फैंकने, नहरों और नदियों को प्रदूषित करने, अवरुद्ध सीवर और नाले, बढ़ते हुए जल और वायु प्रदूषण, पेड़ों और वनों की कटाई, आत्मा की पवित्रता से प्रेरित जीवन की पवित्रता के अनुरुप नहीं हैं। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य लोगों के सोचने की प्रक्रियाओं और कार्यों के रुख और विश्वास में बदलाव लाकर आत्मा और प्रकृति के बीच सद्भाव बहाल करना है। ये सभी आशय व्यावहारिक संशोधन और समग्र विकास अनुरूप हैं।

खुले में शौच करना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छ भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए दो महत्वपूर्ण घटक हैं। खुले में शौच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम चिंता का विषय है, जबकि अपशिष्ट प्रबन्धन शहरी क्षेत्रों की प्रमुख चिंता है। सफाई की खराब स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों के कारण गरीबों के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाले आर्थिक बोझ के सम्बन्ध में स्वास्थ्य के बारे में सबसे प्रमुख चिंता यह है कि स्वच्छ शहरों सहित पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना आज समय की मांग है।

व्यावहारिक परिवर्तनों में शौचालय उपयोग की आदत को बढ़ावा देने, खुले में गंदगी न फैलाने, स्त्रोत पर ठोस कचरे को अलग-अलग करने, खाने से पहले हाथ धोने जैसे व्यवहारों को स्वच्छता आदत में शामिल करने, रिहायशी और कार्य स्थल तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने, लोक स्वच्छता प्रबंधन में जनभागीदारी, पार्क रख-रखाव को शामिल किया जाएगा। वास्तव में रिहायशी और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनाना होगा। स्वच्छ भारत के जारी प्रयासों की सफलता के केंद्र में लोगों को इस विषय में संवेदी बनाना है। असमान विकास पर तीखी टिप्पणी के अतिरिक्त खुले में शौच अपने सम्मान को नकारना है। बाध्यता के कारण यह लोगों की आदत बन गई है। शौचालय बनाने का अवसर मिलने पर कोई भी खुले में शौच करना नहीं चाहेगा। इस व्यवहार का कोई औचित्य नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो यह और अपमानजनक है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दो वर्षों में लगभग 85,000 गांव तथा 141 शहर खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन लांच किए जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 25 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं।

धीमी शुरुआत के बाद स्वच्छ भारत मिशन ने गति हासिल की है और अगले तीन वर्षों में इसकी गति बनाई रखी जाएगी ताकि देश गंदगी की पीड़ा से मुक्त हो सके। हम गर्व के साथ विश्व को 2019 तक स्वच्छ भारत कह सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर स्वच्छता अलख जगाने और स्वच्छ भारत का संकल्प लेने के लिए देश के विभिन्न भागों में अभियान और गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन मुझसे कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को केवल सरकारी कार्यक्रम ही नहीं बल्कि जन-आंदोलन बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। हम इस जन अभियान में लोगों की भागीदारी, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक पहुंचे हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि, उद्योग संस्थान, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो गई हैं।

आत्मा की शुद्धता के भारतीय मूल्य के परिपेक्ष्य में लोग शौचालय बनाने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। अब इस अभियान ने जनस्वरूप ले लिया है। स्वच्छ भारत अब सपना नहीं रहेगा। पसूका

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 75,072 गांवों को खुले में शौच करने के अभिशाप से मुक्ति दिलाई

शिमला/शैल। स्वच्छ भारत अभियान के दो सफल वर्ष पूरे हो जाने पर, संसद सदस्य, हमीरपुर तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किए गए सफल प्रयासों की सराहना की गई। इस अभियान के प्रारम्भ से 2.31 करोड़ शौचालय निर्मित किए गए हैं तथा 75,072 गांवों को खुले में शौच करने के अभिशाप से मुक्ति दिलाई गई है।

अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि 'मैं भारत को खुले में शौच करने के अभिशाप से 2 अक्तूबर, 2019 तक मुक्त करवाने के प्रति नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किए गए प्रयासों की हृदय से सरहाना करता हूं। इस अभियान ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा निर्मित किए गए शौचालयों एवं खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त किए गए गांवों की संख्या की उपलब्धि काफी उत्साहजनक एवं प्रेरणादायी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी गति हम शीघ्र ही स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार कर लेंगे।

इस संबंध में उन्होंने आगे यह कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के कदमों पर चलते हुए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) द्वारा मार्च, 2016 में स्वच्छ हिमाचल-पढ़ाई भी सफाई भी-का अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान को 5000 से अधिक स्कूल के बच्चों एवं राज्य के 25-30 संगठनों की प्रतिभागिता से पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया है। हम इसमें भाग लेने वालों द्वारा अभियान को सफल बनाने एवं राज्य में अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की प्रौन्नति में दिए गए योगदान देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत स्वप्न को साकार रूप देने के लिए नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारम्भ किया गया था।

कारपोरेट कर्मचारियों को नही मिलेगी पैंशन:सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

शिमला/शैल। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रदेश के कारपोरेट सेक्टर के सात हजार कर्मचारियों को पैंशन देने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि 2004 के बाद प्रदेश के निगमों व बोर्डो के कर्मचारियों को पैंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे एस केहर की खंडपीठ ने प्रदेश हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इससे प्रदेश के कारपोरेट सेक्टर के सात हजार के करीब कर्मचारियों को पैंशन मिलने का सपना चकनाचूर हो गया। इन कर्मचारियों में वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर गुस्सा है कि सरकार उनको मिलने वाले लाभों के खिलाफ है व पैंशन का लाभ देने से वंचित कर रही है। कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारी प्रदेश हाईकोर्ट में जंग जीत गए थे व उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पैंशन मिलेंगी। लेकिन सरकार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कारपोरेट कर्मचारी पैंशनर्स संघ के संयोजक व इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभााने वाले पूर्व कर्मचारी नेता गोबिंद चतरांटा ने कहा कि व कानूनविदों से राय लेकर अगला कदम उठाएंगे।

बी सी सी आई पर भारी पड़ सकती है लोढा कमेटी की रिपोर्ट

शिमला/शैल। क्रिकेट को पाक साफ करने के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट में कमेटी ने उनकी सिफारिशों को लागू न करने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष व भाजपा सांसद अनुराग व बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के को बर्खास्त करने का आग्रह कर दिया। इस आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर व शिर्के को फटकार लगाई और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की हिदायतें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीसीसीआई के अधिकारी भगवान की तरह व्यवहार नहीं करे अन्यथा सुप्रीम कोर्ट आदेशों की पालना करवाएगा। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में वित मंत्री अरुण जेटली के बेहद करीबी है। इसके अलावा वह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र है।

गौरतलब हो कि बीसीसीआई ने लोढ़ा पैनल की आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिशों के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय पीठ में प्रधान न्यायाधीश को भी नहीं रखने की भी अपील की थी।

लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीसीसीआई और उसके अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं व अदालत के और लोढ़ा पैनल के सदस्यों के अधिकार को कमतर आंक रहे हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है

जस्टिस ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि बीसीसीआई को अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा। पीठ ने कहा कि कानून की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अदालत बीसीसीआई के रवैये से खुश नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार
उपलब्धियाँ बेमिसाल

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील मार्गदर्शन में

औद्योगिकता से स्वावलम्बन की ओर बढ़े क़दम

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, शांत वातावरण	समयबद्ध अनुमतियां	उद्योग मित्र परिवेश
रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति	आकर्षक प्रोत्साहन	आधारभूत सभी सुविधाएं

वर्तमान कार्यकाल में:

- ₹12,571 करोड़ का निवेश
- 247 औद्योगिक इकाइयाँ स्वीकृत
- 24,760 युवाओं को मिला रोज़गार
- 27,000 युवाओं को रोज़गार मेलों के आयोजन से मिला रोज़गार

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें:- www.himachal.nic.in/industry
सम्पर्क करें:- निदेशक उद्योग/ ज़िला मुख्यालयों में महाप्रबंधक, उद्योग से।

- नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों से सेल व लीज डीड पर स्टॉम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट।
- ज़िला ऊना के पन्डोगा में ₹140 करोड़ की लागत से एवं कन्दरोरी, ज़िला कांगड़ा में ₹122 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला।
- हिमाचल निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही।
- उद्यमियों की सुविधा के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों को GIS के अंतर्गत लाया जाएगा।
- निमंत्रण से उद्योग को बढ़ावा, ₹4079 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त।
- एक ही आवेदन पर नए उद्योगों की स्वीकृतियां 45 दिनों में सुनिश्चित की गईं।
- नए उद्योगों के लिए औद्योगिक इनपुट पर प्रवेश शुल्क 2 से घटकर 1 प्रतिशत किया गया।
- औद्योगिकरण को बढ़ावा के लिए मुख्य मंत्री स्टार्ट-अप/नई औद्योगिक योजना शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत ₹10 लाख तक के ऋण पर 4 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और 15 दिनों में नए उद्योगों का पंजीकरण होगा।

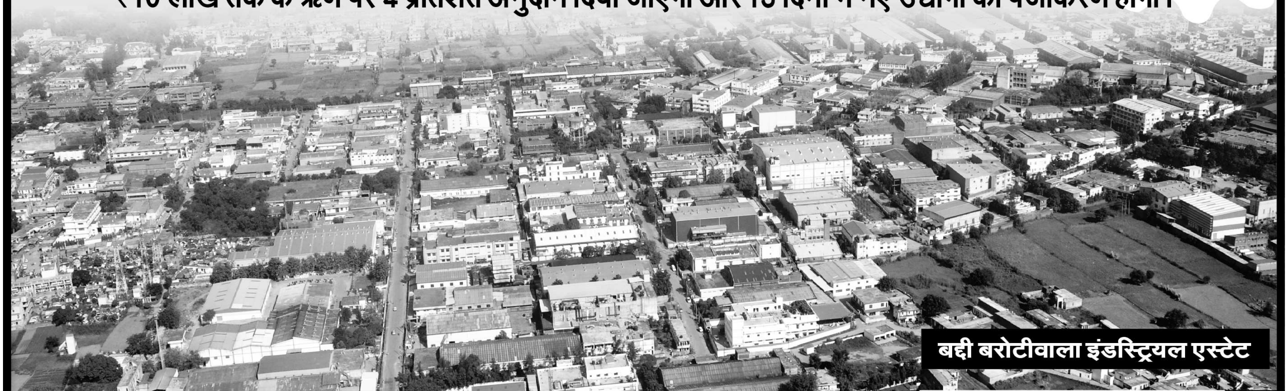

बद्दी बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एस्टेट

हमारा ध्येय: हों रोज़गार के अवसर अपार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भाजपा कार्य समिति में महेश्वर, बालनाहटा, पठानिया, चौधरी तथा रूप सिंह ठाकुर शामिल

शिमला/शैल। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में महेश्वर सिंह, खुशी राम बालनाहटा, राकेश पाठानिया, महन्तराम चौधरी और रूप सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है। इनको ऊना की बैठक के लिये आमन्त्रित भी कर लिया गया है। ऊना में हो रही बैठक में शान्ता कुमार शायद शामिल न हो। कार्यसमिति में शामिल किये गये इन लोगों और शांता की संभावित गैर हाजिरी को लेकर पार्टी के भीतर नये समीकरणों की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। पार्टी के अन्दर शान्ता और धूमल दो विपरीत ध्रुवों के रूप में जाने जाते रहे हैं यह सर्व विदित है। अब केन्द्र में जब प्रचण्ड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आयी है तो भी शान्ता कुमार मोदी सरकार और संगठन को लेकर कितने प्रसन्न रहे है यह उनकी समय-समय पर आयी प्रतिक्रियाओं से जग जाहिर हो चुका है। बल्कि इन प्रतिक्रिओं से यही संदेश गया है कि केन्द्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिल पाने का मलाल उन पर हावि हो चुका है।

इस परिदृश्य में यदि प्रदेश भाजपा का आज आकलन किया जाये तो इसमें धूमल और केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के दो नये ध्रुव बन गये हैं और शांता लगभग हाशिये पर जा चुके हैं। स्मरणीय कि प्रदेश में दो बार शान्ता को मुख्यमन्त्री बनने का मौका मिला और दो ही बार धूमल को। शान्ता दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये और दोनों ही बार विधायक का चुनाव भी हार गये। इसके विपरीत धूमल ने दोनों बार कार्यकाल भी पूरा किया और लगातार चौथी बार विधायक हैं। जबकि धूमल के पहले कार्यकाल में पार्टी के विधायक और मन्त्री ही विरोध और विद्रोह पर उत्तर सदन से गैर हाजिर होने के मुकाम पर जा पंहुचेथे। दूसरे कार्यकाल में तो नाराजगी का एक ऐसा ताना बाना खड़ा हुआ जो हिलोपा के गठन के रूप में सामने आया। संयोगवश दोनो बार इस विरोध और विद्रोह के लिये शान्ता कुमार के आर्शीवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

लेकिन इस बार केन्द्र में इतने प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनने के बाद भी प्रदेश में भाजपा के तेवर उसके अनुरूप नही हैं। प्रदेश में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह इस समय के लिये केन्द्र की जांच ऐजैन्सीयों सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे हैं। वीरभद्र इस जांच के लिये केन्द्र सरकार पर राजनीतिक द्विवेश के साथ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस ढंग से वीरभद्र जनता में अपना पक्ष रख रहे हैं उससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होने की संभावना तक बनती जा रही है। क्योंकि भाजपा की ओर से कोई भी व्यक्ति वीरभद्र प्रकरण को पूरी स्पष्टता के साथ जनता में रख ही नही पा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें स्वयं भी इस मामले की पूरी बारीक समझ नहीं है। संभवत: इसी कारण से भाजपा का कोई भी नेता इस प्रकरण पर वीरभद्र को घेर नही पा रहा है। जबकि प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव इसी मुद्दे पर केन्द्रित रहने की संभावना बनती जा रही है। वीरभद्र इसी मुद्दे को भाजपा के खिलाफ पलटने की पूरी तैयारी मे हैं।

भाजपा ने अभी वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की घोषणा की है और इस आश्य की एक कमेटी भी गठित कर दी है। लेकिन जो आरोप पत्र इससे पहले जारी किया गया था उसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखायी है। इससे यही संदेश जाता है कि पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति नही बल्कि इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विश्वास रखती है। संभवत: इसी कारण से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वीरभद्र के प्रति ज्यादा आक्रामक नही हो पा रहे हैं। ऐसे मे पार्टी चुनावों के लिये किस तरह की रणनीति लेकर आती है उसका अन्दाजा इस बैठक के बाद लग जायेगा। लेकिन इस समय यदि पार्टी वीरभद्र के खिलाफ तीव्र आक्रामकता के तेवर नही अपनाती है तो वीरभद्र उल्टे केन्द्र के खिलाफ आक्रामकता अपनाने का प्रयास करेगें। क्योंकि अभी विक्रमादात्यि ने बंसल आत्महत्या मामले में आये अमित शाह के नाम को जिस तरह से उठाया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है। फिर नड्डा भी संजीब चतुर्वेदी मामले में आगे और घिरते नजर आ रहे हैं। वीरभद्र ने धूमल और एचपीसीए के घेरने के लिये जो भी प्रयास किये हैं वह उल्टे पडे हैं ऐसे में वह अब धूमल मामलों को उछालने की स्थिति में नही है।

इस परिदृश्य में भाजपा के भीतर किस तरह के नये समीकरण उभरते है और उनके केन्द्र में कौन रहता है नड्डा या धूमल या फिर कोई तीसरा चेहरा उभरता है। इसके संकेत कार्यसमिति की इस बैठक में उभर कर सामने आ जायेंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेष्कों की नजर में इस समय वीरभद्र और कांग्रेस को घेरने में धूमल से ज्यादा सशक्त चेहरा भाजपा के पास नही है।

आप के दावों पर पहले ही दिन लगा प्रश्न चिन्ह

आई ए एस राठौर ने किया शामिल होने का खण्डन

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रभावी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह की मौजूदगी में हिमाचल लोकहित पार्टी के उस वर्ग ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है जो भाजपा में नही जा सके थे। स्मरणीय है कि लोकहित पार्टी का गठन भाजपा के ही नाराज लोगों ने पार्टी से बाहर निकलकर किया था। हिलोपा ने प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन विजय केवल महेश्वर सिंह को ही मिल पायी थी। विधानसभा चुनावों में हिलोपा को सुदेश अग्रवाल की समस्त पार्टी से काफी आर्थिक सहयोग भी मिला था। लेकिन हिलोपा प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प नही बन पायी। इसी के साथ ही हिलोपा विखरने लग गयी और इसके दो प्रमुख नेता खुशी राम बालनहटा और टिक्कु ठाकुर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में वापिस आ गये। इसके बाद शेष बची हिलोपा ने आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत शुरू की लेकिन इसमें कुछ लोग विलय के पक्ष में थे तो कुछ सिर्फ मिलकर मोर्चा बनाने की हिमायत कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी इस पर एकमत नही हो सकी तो फिर महेश्वर सिंह और श्यामा शर्मा, गौरव शर्मा के साथ एक बड़ा वर्ग भाजपा में चला गया। इसके बाद अब शेष बचे लोगों ने आप की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिला सोलन में ही हिलोपा का अस्तित्व बचा था और इस विलय के बाद वह पूरी तरह समाप्त हो गया है। हिलोपा के बचे हुए लोगों को एक राजनीतिक ठिकाने की आवश्यकता थी और वह उन्हें अब मिल गया है। यह लोग नये राजनीतिक मंच पर क्या कर पाते हैं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। वैसे हिलोपा के इस तरह के अन्त के लिये यह सभी एक बराबर जिम्मेदार रहे हैं।

हिलोपा के नाम से जो लोग आम आदमी पार्टी में आये हैं उनको लेकर कोई सवाल नही है क्योंकि यह लोग संजय सिंह के साथ पत्रकार वार्ता में शमिल रहे हैं। लेकिन इस पत्रकार वार्ता में हिलोपा से हटकर कुछ और लोगों के शामिल होने की सूची भी महेन्द्र नाथ सोफ्त ने मीडिया के सामने रखी थी। इस सूची में एक सेवानिवृत आई ए एस अधिकारी अमर सिंह राठौर का नाम भी शामिल था। इसके साथ कुछ और सेवा निवृत अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। लेकिन यह लोग पत्रकार वार्ता में शामिल नही थे मीडिया के सामने नही थे। इन लोगों के नाम आने से लोगों में पार्टी की विश्वनीयता और स्वीकार्यता का सन्देश दिया गया था। लेकिन अमर सिंह राठौर आईएएस ने उनका नाम आने के लिये नाराजगी जताई है। उन्होने शैल से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि वह आप में न शामिल हुए है और न ही आप कार्यालय में हुई बैठक में ही उपस्थित थे। उन्होने कहा कि जिन समाचार पत्रों ने उनका नाम छापा है उनको उन्होने इस बारे में सूचित कर दिया है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी रहे व्यक्ति का नाम इस तरह से क्यों इस्तेमाल किया गया। क्या यह सब संजय सिंह को प्रभावित करने के लिये किया गया? क्योंकि अधिकारियों के नामों की सूची मेंआये दूसरे लोगो के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नही है। संयोजकों के इस कदम से पहले ही पार्टी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

हिमाचल में आम आदमी पार्टी को लोक सभा चुनावों के बाद संगठन को लेकर दो बार अपने फैसले बदलने पडे हैं। राजन सुशांत भी जब पार्टी को बड़ा आधार नही दे पाये तो जून में पूरी ईकाई को निलंबित कर दिया गया और दिल्ली से छ:आदमियों की टीम भेजकर उसे संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गयी। लेकिन यह लोग भी कुछ नही कर पाये क्योंकि इन्हे प्रदेश की जानकारी ही नही है। इन लोगों ने भी पुराने लोगों से ही संपर्क साध कर काम चलाने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास के परिणाम सन्तोषजनक नही रहे हैं क्योंकि आप में सक्रिय लोग सोशल मीडिया के दायरे से बाहर नहीं निकल पाये हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थितियां हैं उसमें यदि 'आप' कांग्रेस/भाजपा का विकल्प बनना है तो उसे दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। लेकिन आज तक 'आप' के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर पाये हैं। जो टीम आज भी सामने आयी है उससे भी ऐसी उम्मीद की संभाना कम ही नजर आ रही है। क्योंकि पत्रकार वार्ता में ही 'आप' ने यह कह दिया कि हिमाचल में उनके लिये कांग्रेस चुनौति है भाजपा नहीं। जबकि दूसरी ओर यह तर्क दिया कि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा ही एक दूसरे का विकल्प है। पार्टी का यह आकलन अन्त: विरोधी है और इसी से यह संकेत उभरता है कि हिमाचल को लेकर 'आप' का आकलन अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दस लाख सदस्य जोडने के दावे को लेकर अभी से ही प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गये हैं।

26 स्टोन क्रशरों के खिलाफ ई डी में पंहुची

........पृष्ठ 1 का शेष

जांच के बाद ईडी के चण्डीगढ कार्यालय को अप्रैल 2016 में यह रिपोर्ट भेजकर इस मामले में विधिवत ईसीआई आर दर्ज करने की अनुशंसा की थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह स्टोन क्रशर कई वर्षो से इस तरह के अवैध खनन में संलिप्त रहे है। जो कि सारे संबधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरत तो यह है कि ई डी के चण्डीगढ़ कार्यालय में आज तक इस जांच रिपोर्ट पर कोई कारवाई नही की है। स्मरणीय है कि पिछले दिनो नालागढ क्षेत्र में चल रही अवैध खनन् गतिविधियों पर वहां तैनात पुलिस अधिकारी ने कारवाई की थी तो उसे सरकार ने वहां से बदल दिया था। इस स्थानान्तरण का प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी कडा संज्ञान लिया था। इस स्थानान्तरण को खनन माफिया के प्रभाव में उठाया गया कदम करार दिया गया था। इसी संद्धर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि ईडी के शिमला स्थित जिस अधिकारी ने इन स्टोन क्रशरों के खिलाफ ईडी में मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी उसे भी ईडी से निकालकर वापिस प्रदेश सरकार में भिजवा दिया गया है। उसकी वापसी के लिये अब खनन माफिया की सक्रियता को लेकर भी कुछ हलको में चर्चाएं चल निकली है।

इस मामले में इतनी बडी जांच रिपोर्ट के बाद भी ईडी चण्डीगढ कार्यालय द्वारा अब तक कोई कारवाई न किया जाना चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इसी के साथ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने आगे क्या कारवाई की इसको लेकर बोर्ड की ओर से बताया गया कि इस बारे में उद्योग निदेशालय को सूचना भेज दी गयी है। लेकिन जब स्टेट ज्योलोजिस्टस से इस बारे में बात की गयी तो उसने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ओर से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होने से साफ इन्कार कर दिया। यही नही जब सोलन स्थित खनन अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली गयी तो उसने भी ऐसी कोई सूचना बोर्ड की ओर से आने के बारे में इन्कार कर दिया। यही नहीं जब सोलन स्थित खनन अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली गई तो उसने भी ऐसी कोई सूचना बोर्ड की ओर से आने के बारे में इन्कार कर दिया। इन क्रशरों के खिलाफ अतिरिक्त सीजेएम की अदालत में बोर्ड की तरफ से मामले भेजे गये हैं लेकिन मामले भेजने के बाद भी क्रशर चल रहे हैं। उद्योग विभाग को इसकी कोई जानकारी ही नही है। ईडी का चण्डीगढ़ कार्यालय भी खामोश है। ऐसे में क्या इसे खनन माफिया के प्रभाव के रूप में नही देखा जाना चाहिए।